SARRTHI IAS

LIVE

PRELIMS NAVIGATOR PROGRAM

UPSC PRELIMS 2026

TEST - 33

POLITY

9569093856
ask@sarrthi.com
www.sarrthiias.com
Shop No -6, 2nd Floor, Front Side, Sarrthi IAS,
Near Grover Mithaivala, Bada Bazar Rd, Delhi, 110060

Q1. With reference to the parliamentary and presidential forms of government, consider the following statements:
I. In a presidential system, the head of state and head of government are combined in the office of the president.
II. In a parliamentary system, the legislature can remove the executive branch through a vote of no confidence.
III. Presidential systems generally promote direct accountability of the executive to the people.
How many of the above statements are correct ?
a) Only one
b) Only two
c) All three
d) None

Answer: c) All three
Explanation:
Statement I is correct. In a presidential system, the president is both the head of state and head of government. This is in contrast to a parliamentary system, where these roles are separate. Example: **United States** – In the U.S. presidential system, the President serves as both the head of state and the head of government. The President leads the executive branch, implements laws, and represents the nation in diplomatic matters.
Statement II is correct: A key feature of parliamentary systems is that the executive branch is accountable to the legislature. This accountability is often demonstrated through the ability of the legislature to remove the executive branch with a vote of no confidence. Example: United Kingdom – In the **UK parliamentary system**, the Prime Minister, who is the head of government, can be removed by the House of Commons through a vote of no confidence. If the vote passes, the Prime Minister and the cabinet must resign, leading to either the appointment of a new Prime Minister or a general election.
Statement III is correct: In presidential systems, the president is ,generally, directly elected by the people. This direct election is viewed as promoting direct accountability to the people. Example: **Brazil** – In Brazil's presidential system, the President is directly elected by the people. This direct election method ensures that the President is accountable to the electorate, as the people have the power to choose their leader through regular elections.
Source: Sarrthi Ias class Notes
Difficulty: Moderate

Q2. In the context of the Indian parliamentary system, which of the following principles ***best*** illustrates the nature of ministerial responsibility ?
a) Dual responsibility of ministers to both the President and Prime Minister.
b) Individual responsibility of each minister to the President.
c) Collective responsibility of ministers to the Lok Sabha.
d) Divided responsibility of ministers between the Minister and the judiciary.

प्रश्न1. सरकार के संसदीय और अध्यक्षीय रूपों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अध्यक्षीय प्रणाली में, राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख के पद राष्ट्रपति के पद में संयुक्त होते हैं।
II. संसदीय प्रणाली में, विधायिका अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका शाखा को हटा सकती है।
III. अध्यक्षीय प्रणालियाँ सामान्यतः जनता के प्रति कार्यपालिका की प्रत्यक्ष जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

उत्तर: c) सभी तीन
व्याख्या:
कथन I सही है: अध्यक्षीय प्रणाली में, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है। यह संसदीय प्रणाली के विपरीत है, जहाँ ये भूमिकाएँ अलग-अलग होती हैं। उदाहरण: **संयुक्त राज्य अमेरिका** की अध्यक्षीय प्रणाली में, राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका शाखा का नेतृत्व करते हैं, कानूनों को लागू करते हैं और कूटनीतिक मामलों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कथन II सही है: संसदीय प्रणालियों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कार्यपालिका शाखा विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। यह जवाबदेही प्रायः विधायिका द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका शाखा को हटाने की क्षमता से प्रदर्शित होती है। उदाहरण: **यूनाइटेड किंगडम (UK) की संसदीय प्रणाली** में, प्रधानमंत्री, जो सरकार का प्रमुख होता है, को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट को पद त्याग करना होगा, जिसके बाद या तो नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या आम निर्वाचन होते हैं।
कथन III सही है: अध्यक्षीय प्रणालियों में, राष्ट्रपति, सामान्यतः, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इस प्रत्यक्ष निर्वाचन को जनता के प्रति कार्यपालिका की प्रत्यक्ष जवाबदेही को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता है। उदाहरण: **ब्राजील** की अध्यक्षीय प्रणाली में, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के प्रति जवाबदेह रहे, क्योंकि जनता के पास नियमित निर्वाचनों के माध्यम से अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है।
स्रोत: सारथी IAS क्लास नोट्स
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न2. भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मंत्रियों के उत्तरदायित्व की प्रकृति का ***सर्वोत्तम*** चित्रण करता है?
a) राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के प्रति मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व।
b) राष्ट्रपति के प्रति प्रत्येक मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।
c) लोक सभा के प्रति मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व।
d) मंत्री और न्यायपालिका के बीच मंत्रियों का विभाजित उत्तरदायित्व।

Answer: c) Collective responsibility of ministers to the Lok Sabha.
Explanation:
Option a) is incorrect: Ministers are appointed by the President based on the Prime Minister's advice, but their primary accountability is to the Lok Sabha, not the President. The President's role is more ceremonial, whereas the Lok Sabha holds real legislative and executive power.
Option b) is incorrect:Ministers are not individually responsible to the President. While they hold office during the President's pleasure, real political responsibility lies toward the Lok Sabha, not the President.
Option c) is correct: This is justified because in the Indian parliamentary system, **the principle of collective responsibility,** enshrined in Article 75(3) of the Constitution, ensures that the entire Council of Ministers, including the Prime Minister, is accountable to the Lok Sabha. This means that all ministers are jointly responsible for the government's policies and decisions, presenting a unified stance and maintaining coherence in governance. If the Lok Sabha passes a vote of no confidence, the entire Cabinet must resign, thereby upholding the accountability of the executive branch to the elected representatives of the people and ensuring that the government operates as a cohesive unit.
Option d) is incorrect: Ministers are not accountable to the judiciary for their executive actions. The judiciary's role is to interpret the law and ensure its proper application, not to hold ministers accountable for their policy decisions or administrative actions. The responsibility of ministers is primarily towards the Parliament.
Source: Indian Polity by Laxmikant– Parliamentary form of government
Difficulty: Moderate

Q3. With reference to the features of Federal and Unitary Governments, consider the following statements:
I. A Federal Government has a single government, which may create regional governments.
II. In a Federal Government, powers are divided between the national and regional governments.
III. A Constitution in a Unitary Government is always written.
IV. The legislature in a Unitary Government is always bicameral.
Which of the above statements are ***incorrect***?
a) I and IV only
b) II and III only
c) I, II and III only
d) I, III and IV only

Answer: d) I, III and IV only
Explanation:
Statement I is incorrect: This statement describes a Unitary Government, not a Federal one. In a Unitary Government, a single national government holds all the power and may choose to delegate some authority to regional governments.
Statement II is correct: A defining feature of a Federal Government is the division of powers between the national

उत्तर: c) लोक सभा के प्रति मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व।
व्याख्या:
विकल्प a) सही नहीं है: मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी प्राथमिक जवाबदेही राष्ट्रपति के बजाय लोक सभा के प्रति होती है। राष्ट्रपति की भूमिका अधिक औपचारिक होती है, जबकि वास्तविक विधायी और कार्यकारी शक्ति लोक सभा के पास होती है।
विकल्प b) सही नहीं है: मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। हालांकि वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के बजाय लोक सभा के प्रति होता है।
विकल्प c) सही है: यह उचित है क्योंकि भारतीय संसदीय प्रणाली में, संविधान के अनुच्छेद 75(3) में निहित **सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत** यह सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति जवाबदेह है। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री सरकार की नीतियों और निर्णयों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, एक एकीकृत रुख प्रस्तुत करते हैं और शासन में सामंजस्य बनाए रखते हैं। यदि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो पूरी कैबिनेट को पद त्याग करना पड़ता है, जिससे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति कार्यपालिका शाखा की जवाबदेही बनी रहती है और यह सुनिश्चित होता है कि सरकार एक एकजुट इकाई के रूप में कार्य करती है।
विकल्प d) सही नहीं है: मंत्री अपने कार्यकारी कार्यवाहियों के लिए न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। न्यायपालिका की भूमिका कानून की व्याख्या करना और उसका उचित अनुप्रयोग सुनिश्चित करना है, न कि मंत्रियों को उनके नीतिगत निर्णयों या प्रशासनिक कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना। मंत्रियों का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संसद के प्रति होता है।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- शासन का संसदीय रूप
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न3. संघीय और एकात्मक सरकारों की विशेषताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एक संघीय सरकार में एकल सरकार होती है, जो क्षेत्रीय सरकारों का निर्माण कर सकती है।
II. एक संघीय सरकार में, शक्तियाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित होती हैं।
III. एकात्मक सरकार में संविधान हमेशा लिखित होता है।
IV. एकात्मक सरकार में विधायिका हमेशा द्विसदनीय होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से **सही नहीं** हैं?
a) केवल I और IV
b) केवल II और III
c) केवल I, II और III
d) केवल I, III और IV

उत्तर: d) केवल I, III और IV
व्याख्या:
कथन I सही नहीं है: यह कथन संघीय सरकार के बजाय एक एकात्मक सरकार का वर्णन करता है। एकात्मक सरकार में, एकल राष्ट्रीय सरकार के पास सभी शक्तियाँ होती हैं और वह क्षेत्रीय सरकारों को कुछ प्राधिकार प्रत्यायोजित करने का विकल्प चुन सकती है।

government and the regional governments. This division is usually outlined in a written constitution.
Statement III is incorrect: While many Unitary Governments have written constitutions, it is not a defining characteristic. A Unitary Government's constitution can be either written (like France) or unwritten (like Britain).
Statement IV is incorrect: A Unitary Government can have a legislature with either one or two chambers. The British Parliament, for example, is bicameral (having two chambers), while China's National People's Congress is unicameral (having one chamber).
Source: Indian Polity by Laxmikant– Parliamentary form of government
Difficulty: Moderate

Q4. Consider the following statements:
Statement I: The Governor acts as a representative of the Central Government in each state.
Statement-II: The Indian model of federalism is also called the quasi-federal system.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?
a) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement II explains Statement-I
b) Both Statement-I and Statement-II are correct, but Statement II does not explain Statement-I
c) Statement-I is correct, but Statement-II is incorrect
d) Statement-I is incorrect, but Statement-II is correct

Answer: a) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement II explains Statement-I
Explanation:
Statement I is correct: In India, the **Governor functions as a constitutional link between the Union and the State**. Appointed by the President, the Governor performs certain roles—such as reserving Bills for the President's consideration, reporting constitutional breakdowns, and acting under discretionary powers—that reflect the **influence of the Centre in state governance**.
Statement II is correct: India's federal system is described as **quasi-federal** because, while it has a federal structure (division of powers, written Constitution, independent judiciary), it also contains **strong unitary features** such as a powerful Centre, single Constitution, single citizenship, and emergency provisions.
Statement II correctly explains Statement I: Statement II provides the systemic explanation for Statement I. In a purely federal system, state heads are typically independent of the central authority. However, the Indian model is "quasi-federal" precisely because it incorporates specific unitary features—the primary one being the appointment of the state governor by the Centre—to ensure national unity and central oversight. Therefore, the "quasi-federal" nature of the Constitution is the reason why the Governor is positioned as a representative of the Central Government.
The Governor's role as a link and occasional agent of the Centre in state affairs is **one of the manifestations of India's quasi-federal character**. This institutional design allows the

कथन II सही है: एक संघीय सरकार की एक परिभाषित विशेषता राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। यह विभाजन सामान्यतः एक लिखित संविधान में रेखांकित होता है।
कथन III सही नहीं है: यद्यपि कई एकात्मक सरकारों के पास लिखित संविधान होते हैं, लेकिन यह उनकी एक अनिवार्य विशेषता नहीं है। एकात्मक सरकार का संविधान लिखित (जैसे फ्रांस) या अलिखित (जैसे ब्रिटेन) हो सकता है।
कथन IV सही नहीं है: एकात्मक सरकार में एक सदन या दो सदनों वाली विधायिका हो सकती है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश संसद द्विसदनीय (दो सदन वाली) है, जबकि चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एकसदनीय (एक सदन वाली) है।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- शासन का संसदीय रूप
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राज्यपाल प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जो राज्य के शासन को प्रभावित करता है।
कथन II: भारतीय संघवाद के मॉडल को अर्ध-संघीय प्रणाली भी कहा जाता है।
उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या करता है।
b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, किंतु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या ***नहीं*** करता है।
c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है।
d) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है।

उत्तर: a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है।
व्याख्या:
कथन I सही है: भारत में, **राज्यपाल संघ और राज्य के बीच एक संवैधानिक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राज्यपाल कुछ भूमिकाओं का निर्वहन करता है —जैसे कि राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को आरक्षित करना, संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट करना और विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत कार्य करना—जो **राज्य के शासन में केंद्र के प्रभाव को** दर्शाते हैं।
कथन II सही है: भारत की संघीय प्रणाली को **अर्ध-संघीय** के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि, जहाँ इसमें एक संघीय संरचना (शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका) है, वहीं इसमें एक शक्तिशाली केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधानों जैसी **मजबूत एकात्मक विशेषताएं** भी शामिल हैं।
कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या करता है: कथन II, कथन I की व्यवस्थित व्याख्या प्रदान करता है। विशुद्ध संघीय प्रणाली में, राष्ट्राध्यक्ष सामान्यतः केंद्रीय प्राधिकरण से स्वतंत्र होते हैं। हालांकि, भारतीय मॉडल "अर्ध-संघीय" है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय एकता और केंद्रीय पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट एकात्मक विशेषताएं शामिल हैं-जिनमें से पहला केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। इसलिए, संविधान की "अर्ध-संघीय" प्रकृति ही कारण है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है।

Centre to maintain unity and oversight within a federal framework, thereby explaining why the Governor can influence state governance.
Source: Indian Polity by Laxmikant– Federalism
Difficulty: Tough

Q5. In India, under which of the following circumstances can Parliament make Legislations on State subjects?
I. When Rajya Sabha passes a resolution supported by 2/3rd of the members present and voting.
II. When a proclamation of National Emergency is in operation.
III. When a single State passes a resolution to that effect.
IV. To give effect to international agreements, treaties and conventions.
Select the correct answer from the codes given below:
a) I and III only
b) I and IV only
c) I, II and IV only
d) II, III and IV only

Answer: c) I, II and IV only
Explanation:
Statement I is correct: When Rajya Sabha Passes a Resolution
If the Rajya Sabha declares it is necessary in the national interest for Parliament to legislate on a matter in the State List, Parliament can do so. The resolution must be supported by two-thirds of the members present and voting, and it remains valid for one year, with the possibility of renewal. The laws made by Parliament will prevail over state laws in case of any inconsistency, but states can still legislate on the same matter during the resolution's validity.
Statement II is correct: During a National Emergency
During a National Emergency, Parliament gains the authority to legislate on matters that are ordinarily within the State List. The laws made under this provision become inoperative six months after the emergency ends. While state legislatures retain their power to make laws, any conflict between state and Parliament's laws will result in the central law taking precedence.
Statement III is incorrect: When States Make a Request
When **two or more states pass resolutions** requesting Parliament to legislate on a matter from the State List, Parliament can create laws for those specific states. Other states can later adopt these laws by passing their own resolutions. Once Parliament legislates on such matters, state legislatures lose their power to make laws on them, and only Parliament can amend or repeal the legislation.
Statement IV is correct: To Implement International Agreements
Parliament has the authority to legislate on matters in the State List to implement international treaties, agreements, or conventions. This ensures that the country meets its international obligations and commitments. Examples of

राज्य के मामलों में केंद्र की एक कड़ी और सामयिक प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका **भारत के अर्ध-संघीय चरित्र की अभिव्यक्तियों में से एक है।** यह संस्थागत स्वरुप केंद्र को एक संघीय ढांचे के भीतर एकता और पर्यवेक्षण बनाए रखने की अनुमति देता है, जिससे यह समझाया जा सकता है कि राज्यपाल राज्य शासन को क्यों प्रभावित कर सकता है।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- संघवाद
जटिलता स्तर: कठिन

प्रश्न5. भारत में, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है?
I. जब राज्य सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित एक संकल्प पारित करती है।
II. जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी हो।
III. जब एक एकल राज्य इस आशय का संकल्प पारित करता है।
IV. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, संधियों और सम्मेलनों को प्रभावी करने के लिए।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल I और III
b) केवल I और IV
c) केवल I, II और IV
d) केवल II, III और IV

उत्तर: c) केवल I, II और IV
व्याख्या:
कथन I सही है: जब राज्य सभा एक संकल्प पारित करती है:
यदि राज्य सभा घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद ऐसा कर सकती है। संकल्प को उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, और यह नवीनीकरण की संभावना के साथ एक वर्ष के लिए वैध रहता है। किसी भी विसंगति के मामले में संसद द्वारा बनाए गए कानून राज्य के कानूनों पर अभिभावी होंगे, लेकिन संकल्प की वैधता के दौरान राज्य अभी भी उसी मामले पर कानून बना सकते हैं।
कथन II सही है: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान:
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद को उन मामलों पर कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त होता है जो सामान्य रूप से राज्य सूची के भीतर होते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद अप्रभावी हो जाते हैं। जबकि राज्य विधानसभाएँ कानून बनाने की अपनी शक्ति बनाए रखती हैं, राज्य और संसद के कानूनों के बीच किसी भी संघर्ष के परिणामस्वरूप केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाएगी।
कथन III सही नहीं है: जब राज्य अनुरोध करते हैं:
जब **दो या दो से अधिक राज्य** राज्य सूची से किसी मामले पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करने वाले **संकल्प पारित करते हैं**, तो संसद उन विशिष्ट राज्यों के लिए कानून बना सकती है। अन्य राज्य बाद में अपने स्वयं के संकल्प पारित करके इन कानूनों को अपना सकते हैं। एक बार जब संसद ऐसे मामलों पर कानून बनाती है, तो राज्य विधानसभाएं उन पर कानून बनाने की अपनी शक्ति खो देती हैं, और केवल संसद ही कानून में संशोधन या निरसन कर सकती है।
कथन IV सही है: अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए:
संसद के पास अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का प्राधिकार है। यह सुनिश्चित करता है

such laws include those related to the Geneva Convention, anti-hijacking measures, and environmental regulations.
Source: Indian Polity by Laxmikant- Centre State relations
Difficulty: Moderate

Q6. With reference to Centre-state relations during emergency, consider the following statements:
I. During National Emergency, the state governments are automatically suspended.
II. During President's Rule, the President can promulgate ordinances on state subjects when the Parliament is not in session.
III. During Financial Emergency, Centre can give directions to the states to reduce the salaries of any class of public servant serving in the state.
How many of the above given statements are correct?
a) Only one
b) Only two
c) All three
d) None

Answer: b) Only two
Explanation:
Statement I is incorrect: During the proclamation of a national emergency (under Article 352), the Centre becomes entitled to give executive directions to a state on 'any' matter. Thus, the state governments are brought under the complete control of the Centre, though **they are not suspended**. The federal structure becomes unitary in its operation, but it does not lead to the automatic suspension or dissolution of the state executive or legislature. In contrast, it is during President's Rule (Article 356) that the state executive is dismissed and the state legislature is suspended or dissolved.
Statement II is correct: During President's Rule, the President either suspends or dissolves the state legislative assembly. The Parliament passes the state legislative bills and the state budget. When the Parliament is not in session the President can promulgate ordinances for the governance of the state
Statement III is correct: During the proclamation of a financial emergency (under Article 360), the Centre can issue directions to the states, including: (i) adhering to specified canons of financial propriety, (ii) reducing the salaries and allowances of all public servants in the state, and (iii) reserving all money bills and other financial bills for the consideration of the President.
Source: Indian Polity by Laxmikant- Centre-state relations
Difficulty: Moderate

Q7. To protect the interest of states in financial matters, the Constitution lays down that certain bills can be introduced in the Parliament only on the recommendation of the President. In this context, which of the following are those bills?
I. A bill which imposes or varies any tax or duty in which states are interested.

कि देश अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करे। ऐसे कानूनों के उदाहरणों में जेनेवा कन्वेंशन और पर्यावरण विनियमों से संबंधित कानून शामिल हैं।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- केंद्र-राज्य संबंध
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न6. आपातकाल के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य सरकारें स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं।
II. राष्ट्रपति शासन के दौरान, जब संसद सत्र में ना हो, तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं।
III. वित्तीय आपातकाल के दौरान, केंद्र राज्यों को राज्य में सेवा करने वाले लोक सेवकों के किसी भी वर्ग के वेतन को कम करने का निर्देश दे सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

उत्तर: b) केवल दो
व्याख्या:
कथन I सही नहीं है: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352 के अंतर्गत) की उद्घोषणा के दौरान, केंद्र 'किसी भी' विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार, राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं, हालांकि **वे निलंबित नहीं होती हैं**।
संघीय संरचना अपने कार्यान्वयन में एकात्मक हो जाती है, लेकिन इससे राज्य कार्यपालिका या विधायिका स्वतः निलंबित या विघटित नहीं होती है। इसके विपरीत, राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के दौरान ही राज्य की कार्यपालिका को पदच्युत कर दिया जाता है और राज्य विधानमंडल को निलंबित या विघटित कर दिया जाता है।
कथन II सही है: राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति या तो राज्य विधानसभा को निलंबित कर देते हैं या भंग कर देते हैं। संसद राज्य के विधायी विधेयकों और राज्य के बजट को पारित करती है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति राज्य के शासन के लिए अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं।
कथन III सही है: वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360 के अंतर्गत) की उद्घोषणा के दौरान, केंद्र राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है, जिनमें शामिल हैं: (i) वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांतों का पालन करना, (ii) राज्य में सभी लोक सेवकों के वेतन और भत्तों को कम करना, और (iii) सभी धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- केंद्र-राज्य संबंध
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न7. वित्तीय मामलों में राज्यों के हितों की रक्षा के लिए, संविधान यह निर्धारित करता है कि कुछ विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से वे विधेयक कौन से हैं?
I. एक विधेयक जो किसी ऐसे कर या शुल्क को अधिरोपित करता है या उसमें परिवर्तन करता है जिसमें राज्य का हित निहित हो।
II. एक विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिन पर राज्यों को धन वितरित किया जाता है।

II. A bill which affects the principles on which money is distributed to states.
III. A bill which imposes any surcharge on any specified tax for the purpose of the Centre.
IV. A bill which reduces the salaries and allowances of the members of Rajya Sabha.
Select the correct answer using the codes given below:
a) I and II only
b) I, II, III, and IV
c) I, II and III only
d) III and IV only

Answer: c) I, II and III only
Explanation:
Articles 268 to 293 in Part XII of the Indian Constitution deal with the financial relations between the Centre and the states. The Constitution divides the legislative, executive, and financial powers between the Centre and the states.
Options I, II and III are correct: To safeguard the interests of states in financial matters, the Constitution mandates that the following types of bills can only be introduced in Parliament with the recommendation of the President:

- A bill that imposes or changes any tax or duty that concerns the states.
- A bill that alters the definition of "agricultural income" for the purposes of Indian income tax laws.
- A bill that affects the principles on which money is, or may be, distributed to the states.
- A bill that imposes a surcharge on any specified tax or duty for the Centre's purposes.

Option IV is incorrect: A bill to regulate the salaries and allowances of Members of Parliament can be amended by a simple majority of both Houses of Parliament, without the need for prior recommendation from the President.
Source: Indian Polity by Laxmikant– Centre–state relations
Difficulty: Moderate

Q8. With reference to the recommendations of the Sarkaria Commission, consider the following statements:
I. The residuary powers of taxation should be placed in the State List.
II. The net proceeds of the corporation tax must be shared with the states.
III. The commissioner for linguistic minorities should be activated.
Which of the above statements are correct?
a) I and II only
b) I, II and III
c) I and III only
d) II and III only

Answer: d) II and III only
Explanation:
The Commission made 247 recommendations to improve Centre State relations. The important recommendations are
Statement I is incorrect: The Sarkaria Commission specifically recommended that the residuary powers of

III. एक विधेयक जो केंद्र के उद्देश्य के लिए किसी निर्दिष्ट कर पर कोई अधिभार अधिरोपित करता है।
IV. एक विधेयक जो राज्य सभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों को कम करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल I और II
b) I, II, III और IV
c) केवल I, II और III
d) केवल III और IV

उत्तर: c) केवल I, II और III
व्याख्या:
भारतीय संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को विभाजित करता है।
विकल्प I, II और III सही हैं: वित्तीय मामलों में राज्यों के हितों की रक्षा के लिए, संविधान यह अधिदेशीत करता है कि निम्नलिखित प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते:

- एक विधेयक जो किसी ऐसे कर या शुल्क को अधिरोपित करता है या उसमें परिवर्तन करता है जिसमें राज्य का हित निहित हो।
- एक विधेयक जो भारतीय आयकर कानूनों के उद्देश्यों के लिए "कृषि आय" की परिभाषा में परिवर्तन करता हो।
- एक विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता हो जिनके आधार पर राज्यों को धन वितरित किया जाता है या किया जा सकता है।
- एक विधेयक जो केंद्र के उद्देश्यों के लिए किसी निर्दिष्ट कर या शुल्क पर कोई अधिभार अधिरोपित करता है।

विकल्प IV सही नहीं है: संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता के बिना संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- केंद्र-राज्य संबंध
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न8. सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. कराधान की अवशिष्ट शक्तियों को राज्य सूची में रखा जाना चाहिए।
II. निगम कर की शुद्ध प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
III. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त को सक्रिय किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
a) केवल I और II
b) I, II और III
c) केवल I और III
d) केवल II और III

उत्तर: b) I, II और III
व्याख्या:
आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 247 अनुशंसाएँ की थीं। महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ थी:

taxation should continue to remain with the Parliament. It suggested that only "other" residuary powers (non-taxation) should be moved to the Concurrent List, but taxation powers were to stay at the Union level

Statement II is correct: One of the key financial recommendations of the Commission was that the net proceeds of the corporation tax may be made permissibly shareable with the states,. This was intended to enlarge the divisible pool of taxes to provide more resources to the states

Statement III is correct: The Commission explicitly recommended that the Commissioner for Linguistic Minorities should be activated to more effectively protect the rights and interests of linguistic minority groups

Source: Indian Polity by Laxmikant- Centre-state relations
Difficulty: Moderate

Q9. What would be the ***likely*** impact on Fundamental Rights if a National Emergency is declared on the grounds of armed rebellion?
I. The right to Freedom of Speech and Expression is automatically suspended.
II. The enforcement of right to life and personal liberty can be suspended.
III. The enforcement of right to protection in respect of conviction for certain offenses can be suspended.
Select the correct answer using the code given below:
a) I only
b) I, II and III
c) II and III only
d) None

Answer: d) None
Explanation:

Statement I is incorrect: As per Article 358 the six Fundamental Rights under Article 19 can be suspended only when the National Emergency **is declared on the ground of war or external aggression and not on the ground of armed rebellion**

Statement II is incorrect: While Article 359 allows the President to suspend the right to move any court for the enforcement of Fundamental Rights, the 44th Amendment Act of 1978 introduced a critical exception,. The President cannot suspend the right to move the court for the enforcement of the rights guaranteed by Article 21 (Protection of life and personal liberty) even during an emergency.

Statement III is incorrect:) Similar to the protection afforded to Article 21, the enforcement of **Article 20** (Protection in respect of conviction for offences) **cannot be suspended** by a Presidential Order during any National Emergency. These rights remain enforceable regardless of the grounds on which the emergency was declared

Source: Indian Polity by Laxmikant-Emergency Provisions
Difficulty: Moderate

कथन I सही नहीं है: सरकारिया आयोग ने विशेष रूप से यह अनुशंसा की थी कि कराधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास ही बनी रहनी चाहिए। इसने सुझाव दिया था कि केवल "अन्य" अवशिष्ट शक्तियाँ (गैर-कराधान) समवर्ती सूची में स्थानांतरित की जानी चाहिए, लेकिन कराधान शक्तियाँ संघ स्तर पर ही रहेंगी।

कथन II सही है: आयोग की प्रमुख वित्तीय अनुशंसाओं में से एक यह थी कि निगम कर की शुद्ध प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझाकरणीय बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य राज्यों को अधिक संसाधन प्रदान करने के लिए करों के विभाज्य पूल को बड़ा करना था।

कथन III सही है: आयोग ने स्पष्ट रूप से अनुशंसा की थी कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और हितों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त को सक्रिय किया जाना चाहिए।

स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- केंद्र-राज्य संबंध
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न9. यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ने की ***संभावना*** है?
I. वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है।
II. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है।
III. कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल I
b) I, II और III
c) केवल II और III
d) कोई नहीं

उत्तर: d) कोई नहीं
व्याख्या:

कथन I सही नहीं है: अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत छह मूल अधिकार केवल तभी निलंबित किए जा सकते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल **युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।**

कथन II सही नहीं है: यद्यपि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है, लेकिन 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने एक महत्वपूर्ण अपवाद जोड़ा। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं।

कथन III सही नहीं है: अनुच्छेद 21 को दी गई सुरक्षा के समान ही, **अनुच्छेद 20** (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) के प्रवर्तन को भी किसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार आपातकाल घोषित होने के आधार की परवाह किए बिना लागू रहते हैं।

स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत-आपातकाल प्रावधान
जटिलता स्तर: मध्यम

Q10. With reference to the Presidential Elections in India and USA, consider the following statements:
I. Both India and USA follows a system of Proportional Representation by means of single transferable vote for the Presidential elections.
II. In both of the countries there is no constitutional limit on the number of times a person can be re-elected as President
Which of the statements given above is/are ***incorrect***?
a) I only
b) II only
c) Both I and II
d) Neither I nor II

Answer: c) Both I and II
Explanation:
Statement I is incorrect: India follows a system of Proportional Representation by means of a single transferable vote for its Presidential elections. However, the USA does not use this system. Instead, the USA uses the Electoral College system, where electors from each state cast votes based on the popular vote in their respective states. In the U.S. model, most states (except Maine and Nebraska) follow a "winner-take-all" system, where the candidate winning the popular vote in a state receives all of that state's electoral votes. The U.S. does not use the single transferable vote system for presidential elections.
Statement II is incorrect: The regulations for presidential terms differ significantly between India and the USA. In India, there is no constitutional limit on the number of times a person can be re-elected as President of India; they can serve any number of terms. In USA, the President of the United States is limited to a maximum of two elected four-year terms by the Twenty-second Amendment to the Constitution. A person who serves more than two years of another president's term may only be elected once in their own right, for a maximum total service of 10 year
Source: Sarrthi Ias class Notes
Difficulty: Moderate

Q11. Which of the following is correct in respect of national emergency and President's Rule?
a) In both scenarios, the State government is completely dissolved and controlled by the Centre.
b) During a national emergency, the State executive and legislature continue to function while under the President's Rule, the State executive is dismissed.
c) During a national emergency, the State legislature continues to function while under President's Rule, the State legislature is necessarily dissolved.
d) During a national emergency, the State executive is dismissed while under President's Rule the State executive continues to function.

प्रश्न10. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारत और USA दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करते हैं।
II. दोनों देशों में इस बात की कोई संवैधानिक सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के रूप में पुन: निर्वाचित हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से ***सही नहीं*** है/हैं?
a) केवल I
b) केवल II
c) I और II दोनों
d) न तो I और न ही II

उत्तर: c) I और II दोनों
व्याख्या:
कथन I सही नहीं है: भारत अपने राष्ट्रपति निर्वाचनों के लिए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करता है। हालाँकि, USA इस प्रणाली का उपयोग नहीं करता है; इसके बजाय, USA निर्वाचक मंडल प्रणाली का उपयोग करता है, जहाँ प्रत्येक राज्य के निर्वाचक अपने संबंधित राज्यों में लोकप्रिय मत के आधार पर मतदान करते हैं। अमेरिकी मॉडल में, अधिकांश राज्य (मेन और नेब्रास्का को छोड़कर) "विनर-टेक-ऑल" प्रणाली का पालन करते हैं, जहां एक राज्य में पॉपुलर वोट जीतने वाले उम्मीदवार को उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट प्राप्त होते हैं। अमेरिका, राष्ट्रपति चुनावों के लिए एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का उपयोग नहीं करता है।
कथन II सही नहीं है: भारत और USA के बीच राष्ट्रपति के कार्यकाल के विनियम महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं। भारत में, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के रूप में पुन: निर्वाचित हो सकता है, इस पर कोई संवैधानिक सीमा नहीं है; वे कितनी भी बार सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसके विपरीत, USA में संविधान के 22वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए अधिकतम दो निर्वाचित चार-वर्षीय कार्यकाल की सीमा निर्धारित की गई है। एक व्यक्ति जिसने किसी अन्य राष्ट्रपति के कार्यकाल के दो वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है, उसे अपने अधिकार में केवल एक बार चुना जा सकता है, जिससे कुल सेवा अधिकतम 10 वर्ष हो सकती है।
स्रोत: सारथी IAS क्लास नोट्स
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न11. राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
a) दोनों ही स्थितियों में, राज्य सरकार पूरी तरह से भंग कर दी जाती है और केंद्र द्वारा नियंत्रित की जाती है।
b) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका कार्य करना जारी रखती हैं, जबकि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, राज्य की कार्यपालिका को पदच्युत कर दिया जाता है।
c) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य विधानमंडल कार्य करना जारी रखती है, जबकि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, राज्य विधानमंडल को अनिवार्य रूप से भंग कर दिया जाता है।
d) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य की कार्यपालिका को पदच्युत कर दिया जाता है, जबकि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका कार्य करना जारी रखती है।

Answer: b) During a national emergency, the State executive and legislature continue to function while under President's Rule, the State executive is dismissed.

Explanation:

Option a) is incorrect: In both situations, the Centre exercises increased authority, but under the President's Rule, the State government is fully dissolved, while under a national emergency, the State's powers are only temporarily curtailed. The national emergency effect is that the Centre gets concurrent powers of administration and legislation in the state

Option b) is correct: During National Emergency (Article 352), the state executive and legislature continue to function and exercise the powers granted to them under the Constitution. However, the effect is that the Centre acquires concurrent powers of administration and legislation in the state.

- During the President's Rule (Article 356), the state executive is dismissed, and the state legislature is either suspended or dissolved. The President administers the state through the governor, and Parliament makes laws for the state. In essence, the executive and legislative powers of the state are taken over by the Centre.

Option c) is incorrect: Though during National Emergency (Article 352), the state legislature continues to function and exercise the powers granted to them under the Constitution. Dissolution of the State Legislative Assembly is not necessarily the consequence of the proclamation of the President's rule in a State. The President either suspends or dissolves the state legislative assembly

Option d) is incorrect: During a national emergency, the State executive continues to function while under President's Rule, the State executive is dismissed.

Source: Indian Polity by Laxmikant–Emergency Provisions

Difficulty: Tough

Q12. Consider the following statements:

I. Articles 371 to 371-J of the Indian Constitution contain special provisions for 12 states of India.

II. Special provisions for these twelve states were incorporated through various Presidential Orders.

Which of the statements given above is/are correct?

a) I only

b) II only

c) Both I and II

d) Neither I nor II

Answer: a) I only

Explanation:

Statement I is correct: Articles 371 to 371-J in Part XXI of the Constitution specifically provide special provisions for twelve states, aiming to address various regional, cultural, economic, and administrative needs.

Statement II is incorrect: While special provisions for the erstwhile state of Jammu and Kashmir (under Article 370) were indeed governed or modified via Presidential Orders,

उत्तर: b) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका कार्य करना जारी रखती हैं, जबकि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, राज्य की कार्यपालिका को पदच्युत कर दिया जाता है।

व्याख्या:

विकल्प a) सही नहीं है: दोनों ही स्थितियों में केंद्र अधिक प्राधिकार का उपयोग करता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य सरकार पूरी तरह से भंग हो जाती है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य की शक्तियों में केवल अस्थायी रूप से कटौती की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव यह होता है कि केंद्र को राज्य में प्रशासन और विधान की समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

विकल्प b) सही है: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका कार्य करना जारी रखती हैं और संविधान द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों का प्रयोग करती हैं। हालाँकि, इसका प्रभाव यह होता है कि केंद्र राज्य में प्रशासन और विधान की समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है।

- इसके विपरीत, राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के दौरान, राज्य की कार्यपालिका को पदच्युत कर दिया जाता है, और राज्य विधायिका को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाते हैं और संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। मूलतः, राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ केंद्र द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती हैं।

विकल्प c) सही नहीं है: यद्यपि राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान राज्य विधानमंडल कार्य करना जारी रखती है और संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करती है, लेकिन राज्य विधानसभा का विघटन राष्ट्रपति शासन की घोषणा का आवश्यक परिणाम नहीं है। राष्ट्रपति के पास राज्य विधानसभा को या तो निलंबित करने या भंग करने का विकल्प होता है।

विकल्प d) सही नहीं है: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य की कार्यपालिका कार्य करना जारी रखती है, जबकि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका को पदच्युत कर दिया जाता है।

स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत-आपातकाल प्रावधान

जटिलता स्तर: कठिन

प्रश्न12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से 371-J में भारत के 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।

II. इन बारह राज्यों के लिए विशेष प्रावधान विभिन्न राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से शामिल किए गए थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल I

b) केवल II

c) I और II दोनों

d) न तो I और न ही II

उत्तर: a) केवल I

व्याख्या:

कथन I सही है: संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 371 से 371-J विशेष रूप से बारह राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

the provisions for the twelve states were incorporated through various subsequent Constitutional Amendment Acts, not Presidential Orders. For example:

- Article 371-A (Nagaland) was added by the 13th Amendment Act, 1962.
- Article 371-F (Sikkim) was added by the 36th Amendment Act, 1975,.
- Article 371-J (Karnataka) was inserted by the 98th Amendment Act, 2012.

Source: Indian Polity by Laxmikant- Special Provision for States
Difficulty: Moderate

Q13. Which of the following ***best*** describes the impact of regional parties on Centre–State relations in India?
a) They have posed a challenge to the multiparty system in India
b) They have exacerbated the central government's dictatorial tendencies.
c) They have influenced the central leadership to be more responsive to regional needs.
d) They have solely focused on local issues without affecting centre-state dynamics.

Answer: c) They have influenced the central leadership to be more responsive to regional needs.
Explanation:

- **Option c) is correct:** Regional parties in India have had a profound impact on centre-state relations by influencing the central government to pay more attention to regional demands and concerns. Here's how:
  - Strengthening Federalism: In states like Tamil Nadu (led by parties like DMK and AIADMK) and West Bengal (under TMC), regional parties have demanded greater autonomy for their states, leading to more attention to regional issues at the national level.
  - Coalition Politics: In the 1990s, the National Front government, and the United Progressive Alliance (UPA) government, led by the Congress in the 2000s, relied heavily on regional parties like Trinamool Congress (TMC), Samajwadi Party (SP), and DMK to stay in power. These parties successfully pushed for state-specific issues and regional welfare within national policies.
  - Influence on Policy Making: The Shiv Sena in Maharashtra and the BJP in Assam have pushed for policies that cater to the cultural and linguistic identities of their respective states. This has forced the central

कथन II सही नहीं है: यद्यपि तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 370 के अंतर्गत) वास्तव में राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से शासित या संशोधित किए गए थे, इन बारह राज्यों के प्रावधानों को विभिन्न बाद के संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से शामिल किया गया था, न कि राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से।
उदाहरण के लिए:

- अनुच्छेद 371-A (नागालैंड) को 13वें संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा जोड़ा गया था।
- अनुच्छेद 371-F (सिक्किम) को 36वें संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा जोड़ा गया था।
- अनुच्छेद 371-J (कर्नाटक) को 98वें संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा सम्मिलित किया गया था।

स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न13. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्र-राज्य संबंधों पर क्षेत्रीय दलों के प्रभाव का ***सर्वश्रेष्ठ*** वर्णन करता है?
a) उन्होंने भारत में बहुदलीय प्रणाली के लिए एक चुनौती पेश की है।
b) उन्होंने केंद्र सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों को और बढ़ा दिया है।
c) उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी होने के लिए प्रभावित किया है।
d) उन्होंने केंद्र-राज्य गतिशीलता को प्रभावित किए बिना केवल स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है।

उत्तर: c) उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी होने के लिए प्रभावित किया है।
व्याख्या:
विकल्प c) सही है: भारत में क्षेत्रीय दलों ने केंद्र सरकार को क्षेत्रीय मांगों और चिंताओं पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रभावित करके केंद्र-राज्य संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला है। प्रभाव निम्नलिखित है:

- संघवाद को मजबूत करना: तमिलनाडु (DMK और AIADMK जैसे दलों के नेतृत्व में) और पश्चिम बंगाल (TMC के अंतर्गत) जैसे राज्यों में, क्षेत्रीय दलों ने अपने राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है।
- गठबंधन की राजनीति: 1990 के दशक में नेशनल फ्रंट सरकार और 2000 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार सत्ता में बने रहने के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC), समाजवादी पार्टी (SP) और DMK जैसे क्षेत्रीय दलों पर बहुत अधिक निर्भर थी। इन दलों ने राष्ट्रीय नीतियों के भीतर राज्य-विशिष्ट मुद्दों और क्षेत्रीय कल्याण के लिए सफलतापूर्वक दबाव बनाया।
- नीति निर्धारण पर प्रभाव: महाराष्ट्र में शिव सेना और असम में भाजपा ने उन नीतियों पर बल दिया है जो उनके संबंधित राज्यों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को पूरा करती हैं। इसने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए बाध्य किया है।

स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- राजनीतिक दल

government to consider regional priorities when formulating national policies.

Source: Indian Polity by Laxmikant– Political Parties
Difficulty: Moderate

Q14. Consider the following statements:
I. The Public Accounts Committee has the power to disallow government expenditure.
II. The Estimates Committee examines the budget estimates before they are voted on by Parliament.
III. The Committee on Public Undertakings has members exclusively from the Lok Sabha.
How many of the above statements are correct?
a) Only one
b) Only two
c) All three
d) None

Answer: d) None
Explanation:

- **Statement I is incorrect:** The **Public Accounts Committee (PAC)** does not have the power to disallow or stop government expenditure.
  - Its role is to **scrutinize and report** on public expenditure to ensure that it conforms to parliamentary approval and to highlight irregularities. However, its recommendations are **advisory** and not binding.
- **Statement II is incorrect:** The **Estimates Committee** examines budget estimates **after they have been voted** by Parliament, not before.
  - Its main function is to suggest improvements, economies, and reforms in administration based on the approved budget.
- **Statement III is incorrect:** The Committee on Public Undertakings consists of **members from both Lok Sabha and Rajya Sabha** (15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha).
  - However, the Chairman of the committee is always appointed from amongst the Lok Sabha members, and Rajya Sabha members cannot hold this position.

Source: Current affairs– Parliamentary Committees
Difficulty: Moderate

Q15. The Governor of a state seeks legal advice on a state matter from the Advocate General. Which of the following is ***most*** likely correct?
a) The Advocate General of the state must provide the advice.
b) The Governor must seek advice from the Attorney General of India instead.
c) The Advocate General can refuse to provide advice if it involves confidential matters.

जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. लोक लेखा समिति के पास सरकारी व्यय को अस्वीकार करने की शक्ति है।
II. प्राक्कलन समिति बजट अनुमानों की जांच संसद में मतदान होने से पूर्व करती है।
III. सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्य अनन्य रूप से केवल लोकसभा से होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

उत्तर: d) कोई नहीं
व्याख्या:

- **कथन I सही नहीं है: लोक लेखा समिति (PAC)** के पास सरकारी व्यय को रोकने या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होती है।
  - इसकी भूमिका सार्वजनिक व्यय की **संवीक्षा करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना है** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यय संसदीय अनुमोदन के अनुरूप है तथा अनियमितताओं को उजागर किया जा सके। हालाँकि, इसकी अनुशंसाएँ केवल **सलाहकारी** होती हैं और बाध्यकारी नहीं होतीं।
- **कथन II सही नहीं है: प्राक्कलन समिति** बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा **उन पर मतदान किए जाने के बाद** करती है, न कि पूर्व में।
  - इसका मुख्य कार्य अनुमोदित बजट के आधार पर प्रशासन में सुधार, मितव्ययिता और दक्षता हेतु सुझाव देना है।
- **कथन III सही नहीं है:** सार्वजनिक उपक्रम समिति में **लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य** सम्मिलित होते हैं (15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से)।
  - हालाँकि, समिति का अध्यक्ष सदैव लोकसभा सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, और राज्यसभा सदस्य इस पद को धारण नहीं कर सकते।

स्रोतः करंट अफेयर्स-संसदीय समितियाँ
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न15. किसी राज्य के राज्यपाल राज्य के एक मामले पर महाधिवक्ता (महाधिवक्ता) से विधिक सलाह मांगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ***सर्वाधिक*** संभावित रूप से सही है?
a) राज्य के महाधिवक्ता को अनिवार्य रूप से सलाह प्रदान करनी चाहिए।
b) इसके बजाय राज्यपाल को भारत के महान्यायवादी से अनिवार्य रूप से सलाह लेनी चाहिए।
c) यदि मामले में गोपनीय विषय सम्मिलित हैं, तो महाधिवक्ता सलाह देने से इनकार कर सकते हैं।

d) The Governor must consult the Chief Justice of the High Court before seeking advice.

Answer: a) The Advocate General of the state must provide the advice.
Explanation:
Option a) is correct: The **Advocate General of the state is the highest law officer in the state** and is responsible for providing legal advice to the state government. This role is analogous to the Attorney General of India at the national level.
Article 165 of the Indian Constitution specifically outlines the Advocate General's duty to provide legal advice to the state government upon matters referred to them by the Governor.
Option b) is incorrect: The Attorney General of India deals with matters at the Union level, not the state level. While the Attorney General of India is the highest law officer in the country, their primary role is to advise the central government. The Governor seek advice from the Advocate General on state matters.
Option c) is incorrect: The Advocate General has a duty to advise the government on legal matters referred to them by the Governor, even if they involve confidential matters. The confidential relationship between the Governor and the Advocate General is similar to the confidential relationship between the Governor and the Council of Ministers.
Option d) is incorrect: There is no constitutional requirement for the Governor to consult the Chief Justice of the High Court before seeking legal advice from the Advocate General. The Advocate General is the designated legal advisor to the state government
Source: Indian Polity by Laxmikant– Advocate General
Difficulty: Moderate

Q16. Consider the following provisions concerning the declaration of a Financial Emergency:
I. The satisfaction of the President in declaring a Financial Emergency is not subject to judicial review.
II. Once approved by Parliament, Financial Emergency continues indefinitely until revoked.
III. The approval of the proclamation requires a special majority in both Houses.
How many of the above provisions are correct?
a) Only one
b) Only two
c) All three
d) None

Answer: a) Only one
Explanation:
Statement I is incorrect: While the 38th Amendment Act of 1975 originally made the President's satisfaction final and conclusive, this provision was subsequently deleted by the 44th Amendment Act of 1978. Consequently, the declaration of a Financial Emergency is now subject to judicial review
Statement II is correct: Once the Financial Emergency receives parliamentary approval, it continues indefinitely until revoked by the President. This means there is no

d) सलाह मांगने से पहले राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए।

उत्तर: a) राज्य के महाधिवक्ता को अनिवार्य रूप से सलाह प्रदान करनी चाहिए।
व्याख्या:
विकल्प a) सही है: राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और वह राज्य सरकार को विधिक सलाह प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 विशेष रूप से राज्य सरकार को राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए महाधिवक्ता के कर्तव्य को रेखांकित करता है।
विकल्प b) सही नहीं है: भारत के महान्यायवादी संघ स्तर पर मामलों को देखते हैं, न कि राज्य स्तर पर। यद्यपि वे देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, उनकी प्राथमिक भूमिका केंद्र सरकार को सलाह देना है। राज्यपाल को राज्य के विषयों पर महाधिवक्ता से सलाह लेनी चाहिए।
विकल्प c) सही नहीं है: महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल द्वारा संदर्भित विधिक मामलों पर सरकार को सलाह दे, भले ही उनमें गोपनीय विषय सम्मिलित हों। राज्यपाल और महाधिवक्ता के बीच का गोपनीय संबंध राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के गोपनीय संबंध के समान होता है।
विकल्प d) सही नहीं है: राज्यपाल के लिए महाधिवक्ता से विधिक सलाह लेने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। महाधिवक्ता ही राज्य सरकार का नामित विधिक सलाहकार होता है।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- महाधिवक्ता
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न16. वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:
I. वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।
II. संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इसे वापस नहीं ले लिया जाता।
III. उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त प्रावधानों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

उत्तर: a) केवल एक
व्याख्या:
कथन I सही नहीं है: यद्यपि 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने मूल रूप से राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बना दिया था, लेकिन इस प्रावधान को बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। फलस्वरूप, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

predetermined maximum duration, nor is repeated parliamentary approval needed for its continuation.
Statement III is incorrect: A resolution for the approval of a Financial Emergency can be passed by either House of Parliament by a simple majority only (i.e., a majority of the members of that House present and voting)
Source: Indian Polity by Laxmikant-Emergency Provisions
Difficulty: Moderate

Q17. Which landmark case laid down propositions regarding the imposition of President's Rule under Article 356?
a) Golaknath case
b) Minerva Mills case
c) S. R. Bommai case
d) Kesavananda Bharati case

Answer: c) S. R. Bommai case
Explanation:
Option a) is incorrect: This case (1967) primarily dealt with the amendability of Fundamental Rights. While it had significant implications for the balance of power between the Parliament and the Judiciary, it did not directly address the imposition of President's Rule under Article 356.
Option b) is incorrect: This case (1980) is known for establishing the principle of the 'basic structure' of the Constitution. It reaffirmed judicial review and limited the Parliament's power to amend the Constitution. However, the Minerva Mills case did not specifically lay down propositions on President's Rule.
Option c) is correct: This is the correct answer. The **S.R. Bommai case (1994)** is a landmark judgment that specifically dealt with the imposition of President's Rule under Article 356. The Supreme Court in this case established guidelines and limitations on the President's power to impose President's Rule, emphasizing the federal structure of the Indian Constitution. The significance of the Bommai case is that it "laid down several propositions related to the imposition of President's Rule under Article 356."
Option d) is incorrect: This case (1973) introduced the doctrine of the 'basic structure' of the Constitution. It limited the Parliament's power to amend the Constitution by holding that certain fundamental features of the Constitution cannot be altered. However, the Kesavananda Bharati case did not directly address the issue of President's Rule.
Source: Indian Polity by Laxmikant-Emergency Provisions
Difficulty: Moderate

Q18. Which of the following amendments require ratification by states?
I. Amendments that affect the federal structure.

कथन II सही है: संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इसे वापस नहीं ले लिया जाता। इसका अर्थ है कि इसकी कोई पूर्व निर्धारित अधिकतम अवधि नहीं है, और न ही इसे जारी रखने के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
कथन III सही नहीं है: वित्तीय आपातकाल के अनुमोदन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत (अर्थात, उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत) द्वारा पारित किया जा सकता है। इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत-आपातकाल प्रावधान
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न17. किस ऐतिहासिक मामले में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में प्रस्ताव निर्धारित किए गए थे?
a) गोलकनाथ मामला
b) मिनर्वा मिल्स मामला
c) एस. आर. बोम्मई मामला
d) केशवानंद भारती मामला

उत्तर: c) एस. आर. बोम्मई मामला
व्याख्या:
विकल्प a) सही नहीं है: यह मामला (1967) मुख्य रूप से मूल अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित था। यद्यपि इसके संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ थे, लेकिन इसने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने के विषय को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित नहीं किया था।
विकल्प b) सही नहीं है: यह मामला (1980) संविधान के 'मूल ढांचे' के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। इसने न्यायिक समीक्षा की पुष्टि की और संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित किया। हालाँकि, मिनर्वा मिल्स मामले ने विशेष रूप से राष्ट्रपति शासन पर प्रस्ताव निर्धारित नहीं किए थे।
विकल्प c) सही है: यह सही उत्तर है। **एस. आर. बोम्मई मामला** (1994) एक ऐतिहासिक निर्णय है जो विशेष रूप से अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति पर दिशा-निर्देश और सीमाएँ निर्धारित कीं तथा भारतीय संविधान की संघीय संरचना पर बल दिया। इस मामले का महत्व यह है कि इसने "अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित कई प्रस्ताव निर्धारित किए।"
विकल्प d) सही नहीं है: इस मामले (1973) ने संविधान के 'मूल ढांचे' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसने यह निर्धारित करके संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित किया कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता है। हालाँकि, केशवानंद भारती मामले ने प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन के मुद्दे को संबोधित नहीं किया था।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत-आपातकाल प्रावधान
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न18. निम्नलिखित में से किन संशोधनों के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है?
I. संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधन।

II. Amendments related to the election of the President.
III. Amendments to the powers of the Supreme Court and High Courts.
IV. Amendments related to the Directive Principles of State Policy.
Select the correct answer using the code below:
a) I and II only
b) I, II and III only
c) II, III, and IV only
d) I, II, III, and IV

Answer: b) I, II and III only
Explanation:
Option I is correct: These amendments do require ratification by at least half of the state legislatures. The federalism means that state powers should not be at the mercy of the central government, thus requiring state consultation and consent. These provisions include items related to the distribution of powers between the states and the central government. Provisions affecting the federal relationship between the Union and the States require ratification by at least half of the state legislatures to ensure the federal balance is maintained.
Option II is correct: These amendments do require ratification by at least half of the state legislatures. The election of the President and its manner as a provision that needs state ratification. Since the election of the President involves states (via their MLAs), any change to the procedure for presidential elections affects the federal structure, and thus requires state ratification. Changes to the manner of the President's election (Articles 54 and 55) require state ratification because the President is the head of the federal executive, and states are part of the electoral process.
Option III is correct: These amendments also require ratification by at least half of the state legislatures. The provisions related to the Supreme Court and High Courts are protected in this manner because they directly impact the judiciary's role within the federal system. Alterations to the structure, jurisdiction, or powers of the Union Judiciary and High Courts require state ratification, as they are key elements of the federal judicial system.
Option IV is incorrect: Amendments related to the Directive Principles of State Policy (DPSP) do not require ratification by state legislatures. This type of amendment does not need state ratification, and only amendments related to federal structure, the election of the President, and the powers of the Supreme Court and High Courts require state ratification. The 42nd Amendment, which added new DPSPs, was passed without state ratification.
Source: Indian Polity by Laxmikant-Amendment
Difficulty: Moderate

Q19. With reference to the Indian federal system, consider the following statements:
I. The Indian federal system can be considered as a holding together federation.

II. राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संशोधन।
III. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित संशोधन।
IV. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित संशोधन।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल I और II
b) केवल I, II और III
c) केवल II, III और IV
d) I, II, III और IV

उत्तर: b) केवल I, II और III
व्याख्या:
कथन I सही है: इन संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। संघवाद का अर्थ है कि राज्यों की शक्तियाँ केंद्र सरकार की अनुकंपा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, इसलिए राज्यों के साथ परामर्श और उनकी सहमति अनिवार्य है। इन प्रावधानों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित विषय शामिल हैं। संघ और राज्यों के बीच संघीय संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों को संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
कथन II सही है: इन संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। एक प्रावधान के रूप मेंराष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी विधि जिसके लिए राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। चूँकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य (अपने विधायकों के माध्यम से) शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई भी बदलाव संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, और इस प्रकार राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में परिवर्तन (अनुच्छेद 54 और 55) के लिए राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है क्योंकि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और राज्य निर्वाचन प्रक्रिया का भाग होते हैं।
कथन III सही है: इन संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान इस तरह से संरक्षित हैं क्योंकि वे संघीय प्रणाली के भीतर न्यायपालिका की भूमिका को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। संघ न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों की संरचना, क्षेत्राधिकार या शक्तियों में परिवर्तन के लिए राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे संघीय न्यायिक प्रणाली के प्रमुख तत्व हैं।
कथन IV सही नहीं है: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) से संबंधित संशोधनों के लिए राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के संशोधनों के लिए राज्य अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है; केवल संघीय ढांचे, राष्ट्रपति के निर्वाचन और ***सर्वोच्च न्यायालय*** तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित संशोधनों के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है। 42वां संशोधन, जिसने नए नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा, बिना राज्यों के अनुसमर्थन के पारित किया गया था।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत-संशोधन
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न19. भारतीय संघीय प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारतीय संघीय प्रणाली को एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन माना जा सकता है।

II. In a holding-together federation, powers are predominantly vested in the states.
Which of the statements given above is/are correct ?
a) I only
b) II only
c) Both I and II
d) Neither I nor II

Answer: a) I only
Explanation:
There are two primary ways a federation can be formed:

- **By Integration** ("Coming Together"): Independent, militarily or economically weak states join to form a strong union, such as the United States.
- **By Disintegration** ("Holding Together"): A large unitary state is converted into a federation by granting autonomy to its provinces to promote regional interests and accommodate diversity.

Statement I is correct: India is described as a "holding together" federation, a term popularised by political scientists like Granville Austin.
In this model, the Union is indestructible, and states do not possess the right to secede. The Constitution creates states and can reorganise their boundaries unilaterally (Articles 2–4). This contrasts with a "coming together" federation like the USA, where states voluntarily unite.
Statement II is incorrect: In a holding-together federation, powers are predominantly vested in the Centre, not the states. The Indian Constitution reflects this through:

- A **strong Union List** with more subjects than the State List
- **Residuary powers vested in the Centre** (Article 248)
- Emergency provisions that further centralise power

Predominant state power is a feature of **coming-together federations**, not holding-together ones.
Source: Sarrthi Ias class Notes
Difficulty: Moderate

Q20. How does the representation of states in the Rajya Sabha reflect the asymmetric federalism in India?
a) Each state has equal representation.
b) Representation is based on population with unequal representation among the states.
c) Representation is based on economic contribution of the states.
d) Representation is decided by political bargaining between the political parties which gives the party with more influence more seats.

II. एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, शक्तियाँ मुख्य रूप से राज्यों में निहित होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल I
b) केवल II
c) I और II दोनों
d) न तो I और न ही II

उत्तर: a) केवल I
व्याख्या:
एक संघ के गठन की दो प्राथमिक विधियाँ हैं:

- **एकीकरण द्वारा** ("कमिंग टुगेदर"): स्वतंत्र, सैन्य या आर्थिक रूप से कमजोर राज्य एक मजबूत संघ बनाने के लिए शामिल होते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **विघटन द्वारा** ("होल्डिंग टुगेदर"): एक बड़े एकात्मक राज्य को क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने और विविधता को समायोजित करने के लिए अपने प्रांतों को स्वायत्तता देकर एक संघ में परिवर्तित कर दिया जाता है।

कथन I सही है: भारत को एक "होल्डिंग टुगेदर" फेडरेशन के रूप में वर्णित किया गया है, यह शब्द ग्रैनविले ऑस्टिन जैसे राजनीतिक विज्ञानियों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है।
इस मॉडल में, संघ अविनाशी होता है और राज्यों के पास अलग होने (secede) का अधिकार नहीं होता है। संविधान राज्यों का निर्माण करता है और उनकी सीमाओं को एकपक्षीय रूप से पुनर्गठित कर सकता है (अनुच्छेद 2-4)। यह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे "कमिंग टुगेदर" (साथ आकर बनने वाले) फेडरेशन के विपरीत है, जहाँ राज्य स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।
कथन II सही नहीं है: एक 'होल्डिंग टुगेदर' संघ में, शक्तियाँ मुख्य रूप से केंद्र में निहित होती हैं, न कि राज्यों में। भारतीय संविधान इसे निम्नलिखित माध्यमों से दर्शाता है:

- राज्य सूची की तुलना में अधिक विषयों वाली एक **मजबूत संघ सूची**।
- **अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना** (अनुच्छेद 248)।
- आपातकालीन प्रावधान जो शक्ति को और केंद्रीकृत करते हैं

राज्यों के पास प्रधान शक्ति होना **कमिंग टुगेदर फेडरेशन** की विशेषता है, होल्डिंग टुगेदर की नहीं।
स्रोत: सारथी IAS क्लास नोट्स
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न20. राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व भारत में 'असममित संघवाद' को किस प्रकार दर्शाता है?
a) प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व है।
b) प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है, जिसमें राज्यों के बीच असमान प्रतिनिधित्व होता है।
c) प्रतिनिधित्व राज्यों के आर्थिक योगदान पर आधारित है।
d) प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक सौदेबाजी द्वारा तय किया जाता है, जो अधिक प्रभाव वाले दल को अधिक सीटें देता है।

Answer: b) Representation is based on population with unequal representation among the states.
Explanation:
Asymmetric federalism refers to a federal system of government where different constituent units (states or provinces) possess unequal powers, protections, or representation within the same union. Unlike a symmetric federation where all sub-units have identical status, the Indian model incorporates specific provisions to accommodate the diverse cultural, social, and economic needs of its various regions.
Option b) is correct: The representation of states in the Rajya Sabha reflects the asymmetrical federalism in India because it is based on population, leading to unequal representation among the states.
Unequal Representation: The Rajya Sabha does not follow the principle of equal representation of states. Instead, states are given seats based on their population. This results in a variance in the number of representatives each state has, from 1 to 31. For example, Uttar Pradesh has 31 members while states like Tripura have only 1.
Contrast with Symmetrical Federalism: This contrasts with the symmetrical federalism seen in the United States, where each state has equal representation in the Senate. The American Senate has 100 members, with two from each state.
Population-Based Allocation: The allocation of seats in the Rajya Sabha is determined by the population of each state, as per the Fourth Schedule of the Constitution. This means that more populous states get more representatives than less populous ones. The representatives of states in the Rajya Sabha are elected by the elected members of state legislative assemblies.
No Agreement Among States: The Indian federation is not based on an agreement between the states, unlike some other federations. This contributes to the asymmetrical nature of Indian federalism.
Differential Treatment: The Indian Constitution provides for differential treatment to many states, which is another aspect of its asymmetrical federalism. This is in contrast to the principle of equality between states that is seen in some other federations.
Source: Indian Polity by Laxmikant-Elections
Difficulty: Moderate

Q21. Consider the following statements:
I. Education was originally a subject in the State List in the Indian Constitution.
II. The 42nd Amendment Act, 1976 transferred "Education" from the State List to the Union List.
III. If a state law on education conflicts with a central law under Article 246, the State law prevails in all circumstances.
How many of the above statements are correct?
a) Only one
b) Only two
c) All three
d) None

उत्तर: b) प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है, जिसमें राज्यों के बीच असमान प्रतिनिधित्व होता है।
व्याख्या:
असममित संघवाद सरकार की एक संघीय प्रणाली को संदर्भित करता है जहां विभिन्न घटक इकाइयों (राज्यों या प्रांतों) के पास एक ही संघ के भीतर असमान शक्तियां, संरक्षण या प्रतिनिधित्व होता है। एक सममित संघ के विपरीत जहां सभी उप-इकाइयों का समान दर्जा होता है, भारतीय मॉडल अपने विभिन्न क्षेत्रों की विविध सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को समायोजित करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करता है।
विकल्प b) सही है: राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व भारत में असममित संघवाद को दर्शाता है क्योंकि यह जनसंख्या पर आधारित है, जिससे राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व में असमानता होती है।
असमान प्रतिनिधित्व: राज्यसभा राज्यों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। इसके बजाय, राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या में अंतर होता है, जो 1 से 31 तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य हैं जबकि त्रिपुरा जैसे राज्यों के पास केवल 1 सदस्य है।
सममित संघवाद से विरोधाभास: यह संयुक्त राज्य अमेरिका में देखे जाने वाले सममित संघवाद के विपरीत है, जहाँ सीनेट में प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व होता है। अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य से दो सदस्य होते हैं।
जनसंख्या-आधारित आवंटन: संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका अर्थ है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को कम जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं: अन्य संघों के विपरीत, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते पर आधारित नहीं है। यह भारतीय संघवाद की असममित प्रकृति में योगदान देता है।
विभेदकारी व्यवहार: भारतीय संविधान कई राज्यों के लिए विभेदकारी व्यवहार का प्रावधान करता है, जो इसके असममित संघवाद का एक अन्य पहलू है। यह राज्यों के बीच समानता के सिद्धांत के विपरीत है जो कुछ अन्य संघों में देखा जाता है।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत-निर्वाचन
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न21. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. शिक्षा मूल रूप से भारतीय संविधान की राज्य सूची का विषय था।
II. 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने "शिक्षा" को राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित कर दिया।
III. यदि शिक्षा पर राज्य का कानून अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्रीय कानून के साथ संघर्ष में होता है, तो सभी परिस्थितियों में राज्य का कानून अभिभावी होगा।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

Answer: a) Only one
Explanation:
Statement I is correct: Education was originally a subject in the State List (List II) of the Seventh Schedule of the Indian Constitution. Before the year 1976, education was indeed a subject enumerated in the State List (List II) of the Seventh Schedule. This gave states exclusive power to legislate on educational matters in normal circumstances.
Statement II is incorrect: The 42nd Amendment Act of 1976 transferred education from the State List to the Concurrent List, not the Union List. The Concurrent List allows both the central and state governments to make laws on the subject.
Statement III is incorrect: While Article 246 deals with the subject matter of laws made by the Parliament and State Legislatures, in the case of a conflict between a central law and a state law on a subject in the Concurrent List, the central law generally prevails. However, there is an exception: if the state law has been reserved for the consideration of the President and has received their assent, then the state law prevails in that state. The Parliament can still override such a state law by subsequently making a law on the same matter.
Source: Sarrthi Ias Class Notes
Difficulty: Moderate

Q22. According to the special provisions for Mizoram under Article 371-G of the Indian Constitution, the state's legislative assembly is granted protection from automatic application of Acts of Parliament over certain matters. In this context, consider the following:
I. Religious or social practices of the Mizos.
II. Mizo customary law and procedure.
III. Ownership and transfer of land.
Which of the above matters are protected by the state's legislative assembly?
a)I and III only
b) II and III only
c) I, II and III only
d) II only

Answer: c) I, II and III only
Explanation:
According to the special provisions for Mizoram under Article 371-G of the Indian Constitution, the state's legislative assembly is granted protection over the following matters:

- **Religious or social practices of the Mizos.**
- **Mizo customary law and procedure.**
- Administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law.
- **Ownership and transfer of land.**

These protections mean that Acts of Parliament relating to these specific matters do not automatically apply to Mizoram unless the State Legislative Assembly of Mizoram decides to adopt them. This demonstrates a commitment to respecting the unique social, cultural, and legal systems of the Mizo people. This also illustrates how the Indian

उत्तर: a) केवल एक
व्याख्या:
कथन I सही है: शिक्षा मूल रूप से भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) का विषय था। वर्ष 1976 से पहले, शिक्षा वास्तव में सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) में सूचीबद्ध एक विषय था। इसने राज्यों को सामान्य परिस्थितियों में शैक्षिक मामलों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति दी।
कथन II सही नहीं है: 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया था, न कि संघ सूची में। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की अनुमति देती है।
कथन III सही नहीं है: यद्यपि अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय से संबंधित है, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में, सामान्यतः केंद्रीय कानून अभिभावी होता है। हालांकि, एक अपवाद है: यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया है और उनकी सहमति प्राप्त हो गई है, तो उस राज्य में राज्य का कानून अभिभावी होता है। संसद अभी भी उसी मामले पर बाद में कानून बनाकर इस तरह के राज्य कानून को अध्यारोहित कर सकती है।
स्रोत: सारथी IAS क्लास नोट्स
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न22. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371-G के अंतर्गत मिजोरम के विशेष प्रावधानों के अनुसार, राज्य की विधानसभा को कुछ मामलों में संसद के अधिनियमों के स्वतः लागू होने से सुरक्षा प्रदान की गई है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
I. मिज़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ।
II. मिज़ो प्रथागत कानून और प्रक्रिया।
III. भूमि का स्वामित्व और हस्तांतरण।
उपर्युक्त में से कौन से मामले राज्य की विधानसभा द्वारा संरक्षित हैं?
a) केवल I और III
b) केवल II और III
c) I, II और III
d) केवल II

उत्तर: c) I, II और III
व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371-G के अंतर्गत मिजोरम के लिए विशेष प्रावधानों के अनुसार, राज्य की विधानसभा को निम्नलिखित मामलों पर संरक्षण प्रदान किया गया है:

- **मिज़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ।**
- **मिज़ो प्रथागत कानून और प्रक्रिया।**
- मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार निर्णयों से जुड़े सिविल और आपराधिक न्याय का प्रशासन।
- **भूमि का स्वामित्व और हस्तांतरण।**

इन संरक्षणों का अर्थ है कि इन विशिष्ट मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम मिजोरम पर तब तक स्वतः लागू नहीं होते, जब तक कि मिजोरम की राज्य विधानसभा उन्हें अपनाने का निर्णय नहीं लेती। यह मिज़ो लोगों की विशिष्ट

Constitution accommodates regional diversity within its federal structure.
Source: Indian Polity by Laxmikant– Special Provisions for some States
Difficulty: Moderate

Q23. With reference to the Indian Constitution, consider the following statements
I. The Indian Constitution is the lengthiest in the world.
II. The Union List has a larger number of subjects than the State List
III. India follows a bicameral legislative system at the state level but not at the central.
How many of the above statements are correct?
a) Only one
b) Only two
c) All three
d) None

Answer: b) Only two
Explanation:
Statement I is correct: The Indian Constitution is the lengthiest written Constitution in the world. It contains a large number of Articles, Schedules, and detailed provisions covering governance, federal relations, emergency powers, and administrative details. This length is due to India's diversity, borrowed constitutional features, and the need for clarity in a newly independent nation.
Statement II is correct: The Union List has more subjects than the State List.
Union List: 100 subjects (originally 97; expanded over time)
State List: **61 subject**s (Originally 66, decreased over time)
This reflects the strong centralising bias of the Indian Constitution, consistent with India being a holding-together federation.

STRUCTURE OF THE THREE LISTS UNDER 7TH SCHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION

LIST	ORIGINAL SUBJECTS	CURRENT SUBJECTS	EXAMPLES OF SUBJECTS
UNION LIST (LIST I)	97	100	Defence, Foreign Affairs, Atomic Energy, Railways, Currency, Banking, Inter-state Trade, Income Tax, Customs, etc.
STATE LIST (LIST II)	66	61	Police, Public Order, Public Health, Agriculture, Local Government, Land, Fisheries, Trade, etc.
CONCURRENT LIST (III)	47	52	Education, Forests, Marriage and Divorce, Adoption, Bankruptcy, Labour welfare, Criminal Law, etc.

Statement III is incorrect: India does not follow a bicameral system at the State level uniformly, and it does follow bicameralism at the Centre. At the Centre: Parliament is bicameral (Lok Sabha + Rajya Sabha). At the State level, Bicameralism is optional, not mandatory. Only a few states (e.g., Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh) have Legislative Councils.
Source: Sarrthi Ias Class Notes
Difficulty: Moderate

सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी प्रणालियों के सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, यह यह भी स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान अपनी संघीय संरचना के भीतर क्षेत्रीय विविधता को किस प्रकार समायोजित करता है।
स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न23. भारतीय संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
I. भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है।
II. संघ सूची में विषयों की संख्या राज्य सूची की तुलना में अधिक है।
III. भारत राज्य स्तर पर द्विसदनीय विधायी प्रणाली का पालन करता है, किंतु केंद्र स्तर पर नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

उत्तर: b) केवल दो
व्याख्या:
कथन I सही है: भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें बड़ी संख्या में अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और शासन, संघीय संबंधों, आपातकालीन शक्तियों और प्रशासनिक विवरणों को कवर करने वाले विस्तृत प्रावधान सम्मिलित हैं। यह विस्तार भारत की विविधता, उधार ली गई संवैधानिक विशेषताओं और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र में स्पष्टता की आवश्यकता के कारण है।
कथन II सही है: संघ सूची में राज्य सूची की तुलना में अधिक विषय हैं।
संघ सूचीः 100 विषय (मूल रूप से 97; समय के साथ विस्तारित)
राज्य सूचीः **61 विषय** (मूल रूप से 66, समय के साथ घटते गए)
यह भारतीय संविधान के मजबूत केंद्रीकरण झुकाव को दर्शाता है, जो भारत के 'होल्डिंग-टुगेदर' संघ होने के अनुरूप है।

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत तीन सूचियों की संरचना

सूची	मूल विषय	वर्तमान विषय	विषयों के उदाहरण
संघ सूची (सूची I)	97	100	रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग, अंतर-राज्य व्यापार, आयकर, सीमा शुल्क, आदि
राज्य सूची (सूची II)	66	61	पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार, भूमि, मत्स्य पालन, व्यापार, आदि
समवर्ती सूची (सूची III)	47	52	शिक्षा, वन, विवाह और तलाक, गोद लेना, दिवालियापन, श्रम कल्याण, आपराधिक कानून, आदि

कथन III सही नहीं है: भारत राज्य स्तर पर समान रूप से द्विसदनीय प्रणाली का पालन नहीं करता है, और यह केंद्र में द्विसदनीयता का पालन करता है। केंद्र में: संसद द्विसदनीय है (लोकसभा + राज्यसभा)। राज्य स्तर पर: द्विसदनीयता वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। केवल कुछ राज्यों (जैसे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश) में विधान परिषदें हैं।
स्रोत: सारथी IAS क्लास नोट्स
जटिलता स्तर: मध्यम

Q24. Which of the following ***best*** describes the nature of the Indian Constitution during a National emergency?
a) Federal
b) Quasi-federal
c) Unitary
d) Confederal

Answer: c) Unitary
Explanation:
Option c) is correct: The Indian Constitution is described as having a **federal structure with a unitary bias**. This means that while it establishes a federal system with a division of powers between the Union and the States, it also contains numerous unitary features that give more power to the Centre.

- During a National emergency, this **federal structure transforms into a unitary one**. This transformation happens without a formal amendment to the Constitution.
- The Constitution of India is designed to be both unitary and federal depending on the requirements of time and circumstances. In normal times, it functions as a federal system, but during an emergency, it is designed to work as though it was a unitary system.
- During a National Emergency, the **executive power of the Union extends to directing any state** regarding the manner in which its executive power is to be exercised. The central government is empowered to give directions to a state on 'any' matter.

Source: Indian Polity by Laxmikant- Emergency
Difficulty: Moderate

Q25. Which of the following provisions was ***not*** introduced by the 44th Constitutional Amendment in the context of the emergency?
a) The term "internal disturbance" was replaced by "armed rebellion" in respect of national emergency.
b) The President can declare a national emergency only on the written recommendation of the cabinet.
c) It added the provision that the proclamation of national emergency can be declared for a specified part of territory of India.
d) It provided that the fundamental rights guaranteed by Articles 20 and 21 cannot be suspended during a national emergency.

Answer: c) It added the provision that the proclamation of national emergency can be declared for a specified part of territory of India.
Explanation:
Option a) is incorrect: Originally, "internal disturbance" was the third ground for a National Emergency. The **44th Amendment Act of 1978** replaced this vague term with "armed rebellion" to prevent the misuse seen in 1975.

प्रश्न24. निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान की प्रकृति का ***सर्वोत्तम*** वर्णन करता है?
a) संघीय
b) अर्ध-संघीय
c) एकात्मक
d) परिसंघीय

उत्तर: c) एकात्मक
व्याख्या:
विकल्प c) सही है: भारतीय संविधान को **एकात्मक झुकाव वाली संघीय संरचना** के रूप में वर्णित किया गया है। इसका अर्थ है कि जहाँ यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है, वहीं इसमें कई एकात्मक विशेषताएँ भी सम्मिलित हैं जो केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करती हैं।

- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यह **संघीय संरचना एकात्मक संरचना में परिवर्तित हो जाती है**। यह परिवर्तन संविधान में किसी औपचारिक संशोधन के बिना होता है।
- भारत का संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के आधार पर एकात्मक और संघीय दोनों होने के लिए बनाया गया है। सामान्य समय में, यह एक संघीय प्रणाली के रूप में कार्य करता है, लेकिन आपातकाल के दौरान, इसे एक एकात्मक प्रणाली के रूप में काम करने के लिए बनाया गया है।
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, **संघ की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को यह निर्देश देने तक विस्तृत हो जाती है** कि उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार किसी राज्य को 'किसी भी' विषय पर निर्देश देने के लिए सशक्त होती है।

स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत- आपातकाल
जटिलता स्तर: मध्यम

प्रश्न25. आपातकाल के संदर्भ में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ***नहीं*** जोड़ा किया गया था?
a) राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में "आंतरिक अशांति" शब्द को "सशस्त्र विद्रोह" से प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
b) राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
c) इसने यह प्रावधान जोड़ा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के क्षेत्र के एक निर्दिष्ट हिस्से के लिए घोषित की जा सकती है।
d) इसने प्रावधान किया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है।

उत्तर: c) इसने यह प्रावधान जोड़ा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के क्षेत्र के एक निर्दिष्ट हिस्से के लिए घोषित की जा सकती है।
व्याख्या:
विकल्प (a) सही नहीं है: मूल रूप से, "आंतरिक अशांति" राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का तीसरा आधार था। **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** ने 1975 में देखे गए दुरुपयोग को रोकने के लिए इस अस्पष्ट शब्द को "सशस्त्र विद्रोह" से प्रतिस्थापित कर दिया।

Option b) is incorrect: The President can now only proclaim a National Emergency after receiving a written recommendation from the Cabinet (the Prime Minister and other ministers of cabinet rank). This safeguard was added by the **44th Amendment** to ensure the Prime Minister alone cannot make the decision.

Option c) is the correct answer: The **42nd Constitutional Amendment Act of 1976** enabled the **President of India to declare a National Emergency for a specific part of the country.** This is in addition to the ability to declare a National Emergency for the entire country.

Option d) is incorrect: The **44th Amendment** provided that, during a national emergency, the fundamental rights guaranteed by Articles 20 and 21 cannot be suspended.

- Restored some of the powers of the Supreme Court and High Court.
- Made certain procedural safeguards with respect to President's Rule and National Emergency.

Source: Indian Polity by Laxmikant–Amendment
Difficulty: Tough

विकल्प (b) सही नहीं है: अब राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल (प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों) से लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। यह सुरक्षा उपाय प्रावधान **44वें संशोधन** द्वारा जोड़ा गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की प्रधानमंत्री अकेले यह निर्णय न ले सकें।

विकल्प c) सही उत्तर है: 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के **राष्ट्रपति को देश के एक विशिष्ट हिस्से के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने में** सक्षम बनाया था। यह पूरे देश के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की क्षमता के अतिरिक्त था।

विकल्प d) सही नहीं है: 44वें संवैधानिक संशोधन ने प्रावधान किया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

- इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को बहाल किया।
- इसने राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए।

स्रोत: भारतीय राजव्यवस्था - लक्ष्मीकांत-संशोधन
जटिलता स्तर: कठिन

SARRTHI IAS

Prepare for UPSC CSE 2026

Credible Faculty | **Quality Content** | **Affordable Courses**

Dr. Shivin Chaudhary

Varun Jain

Mudit Jain

Contact Us

95690 93856

ask@sarrthi.com

www.sarrthiias.com

Sarrthi IAS

Sarrthi IAS